Minister of the Government of India rang me up and said that for the last three years he was trying to see that all these retrenched workers were reinstated but could not succeed because there were a number of difficulties. He said that he was happy that I had done it today. Therefore, with that achievement I will be able to appeal to the workers that they must augment the resources, improve production, improve efficiency and the performance should be far better. It does not depend upon the emergency. Thus in the coming year we are going to establish that even without the imposition of emergency in the country but with the willing co-operation of the workers in this country and by holding consultations with the trade unions, efficiency and discipline and the strength of the railways can be improved. That will be the task and objective with which I will try to function.

THE BUDGET (GENERAL) 1977-78 —*General Discussion*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): We shall now take up the General Discussion on the General Budget, Mr. Kureel.

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जहां तक बजट का ताल्लुक है, मुझे कुछ कहना नहीं है । उस पर मुझे कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इन्टरिम बजट है । आगे जब जनता पार्टी का बजट आयेगा उस पर हम कुछ कह सकेंगे ।

फिर भी दो-तीन बातों की तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यह जनता सरकार जो बनी है यह भानमती का कुनबा है जो मुख्तलिफ आइडियोलौजी वाली पार्टियों से बना है । हमारी छोटी-छोटी गलतियों को लेकर, हमारी छोटी-छोटी कमजोरियों को ले कर इन लोगों ने जो शीशमहल बनाया है वह किसी भी वक्त चाकनाचूर हो सकता है । यह मैं बता देना चहता हूं और खुले तौर पर बता देना चाहता हूं कि यह इन की कामयाबी नहीं है, इन की पालिसियों की कामयाबी नहीं है, इन की अपनी पार्टी की कामयाबी नहीं है । आज तक ये जमातें आपस मे लड़ती रही हैं और जो गवर्नमेंट मे बैठे हुए हैं...

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the Finance Minister is not here. He should be here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): The Finance Minister is busy in the other House.

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : पटेल साहब दूसरे सदन में काम मे लगे हैं । वे चन्द मिनटों मे आ जायेंगे ।

श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ तालिब : फाइनेंन्स मिनिस्टर को ही नहीं, सब मिनिस्टरों को यहां होना चाहिए । कोई भी मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं है । मैं कहना चाहता हू जनता पार्टी के लोग जो आपस मे लड़ते थे, आपस मे एक दूसरे का सिर फोड़ते थे इकट्ठा हो कर इन्होंने एक ऐसी पार्टी को हराने की कोशिश की है जिसका कुछ इतिहास है, जिस ने बड़े-बड़े काम किये हैं । मैं आजादी की बात नहीं कहना चाहता हूं । उस पार्टी ने हिन्दुस्तान को यूनीफाई किया है, आजादी के बाद तमाम रियासतों को हिन्दुस्तान में शामिल किया । जो काम पटेल ने किय देशी रियासतों को हिन्दुस्तान के अन्दर मिला कर वह काम कोई पार्टी नहीं कर सकती थी । जमींदारी को मिटाया और गरीबों को, काश्तकारों को भूमि पर अधिकार दिया । जो सीरदार थे उन को भी भूमिधर बनाया ।

मैं पूछना चाहता हूं कि कमजोर जातियों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शैडॅयूल्ड ट्राइब्स के लिए इन पार्टियों के पास क्या प्रोग्राम था ?

[श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ़ तालिब]

आज कोई पार्टी कह सकती है कि उस ने अपनी पार्टी का सदर हरिजन को बनाया है। आज हमारी पार्टी है जिसने दो हरिजनों को अपना सदर बनाया है। एक तो जगजीवनराम जी है जो आज आप के साथ है और दूसरे है संजीवैय्या जी। हमारी पार्टी ने जनरल सेक्रटरी हरिजनों को बनाया है। आज हमारी पार्टी में सेपरेट सेल्स है हरिजनों की उन्नति के लिए। यही नहीं, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में और तमाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों में हरिजनों को उठाने के लिए उन के सेल्स अलग मौजूद है जो आये दिन हरिजनों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करते है। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थीं, जिन्होंने इस मुल्क के मस्तक को ऊंचा किया सारी दुनिया में और सारी दुनिया ने उन की ताकत को माना और अमरीका भी हिन्दुस्तान से डरा और दुनिया की दूसरी ताकतें भी हिन्दुस्तान का लोहा मानने लगीं उन्होंने अपने वक्त में हरिजनों के लिए जो प्रोग्राम रखा वह काफी बेहतर था। उन्होंने बांडेड लेबर को खत्म किया। गरीब हरिजनों के बच्चों को सौ रुपये में या कुछ पैसे दे कर खरीद लिया जाता था और बूढ़े होने तक वह उन की गुलामी करते थे, अपने खरीदार की गुलामी करते थे और उन के बाद उन के बच्चे और पोते उनकी गुलामी करते थे। सदियों से यह काम चला आ रहा था। किसी पार्टी ने क्या इस को खत्म करने की बात सोची थी। कितने लोग थे कि जो बांडड लेबर को जानते थे ? मैं हरिजनों का सब से पुराना मेम्बर हूं। मैं केन्द्रीय असेम्बली में भी रहा हूं। मैं जानता हूं कि किसी पार्टी ने हरिजनों, कमजोर और गिरे हुए तबकों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इन-डेटेडनेस जो सदियों से चली आ रही थी उस में सूद दर सूद उन से लिया जाता था और इस तरह से एक बार उन को कुछ पैसा दे कर जिन्दगी भर उन को गुलाम बनाये रखा जाता था, हमारी कांग्रेस सरकार ने उस को खत्म किया। हमारी पार्टी ने भूमिहीनों को जमीनें दीं और उन गरीब लोगों को छोटे छोटे धंधे चलाने के लिए लोन दिये। उन के लिए बिना सूद के लोन का इंतजाम किया और सिंचाई के लिए छोटे किसानों के सामने तरह तरह की स्कीमें रखीं। उन को लोन देने की स्कीमें बनाई गईं और यह सब करने वाली, श्रीमती इन्दिरा गांधी को हम ने हरा दिया। आप कहेंगे कि उन को आप ने हराया है। लेकिन आप के सामने क्या प्रोग्राम था। एक हवा चली जिस में देश के वेस्टेड इंटरेस्ट और ब्योरोक्रेसी मिल कर एक हो गई और अपने चन्द जाती मतानबात की वजह से, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से गवर्नमेंट इंप्लाईज बोनस के सवाल को ले कर नाराज हो गये और बड़े अफसर इस लिए नाराज हो गये कि वह नहीं चाहते थे कि यहां के बुनियादी आर्थिक ढांचे में कोई तब्दीली आये। वह अफसर जानते थे कि वे लोग अफसर है और उन के लड़के भी अफसर हो जायेंगे। वह अंग्रजी बोलना जानते है और इसीलिए इंटरव्यू में दो, तीन सौ नम्बर रखें जाते है। उस की वजह से ही जो काबिल है वे पीछे रह जाते है और जो काबिल नहीं है वह आगे बढ़ जाते है। दो सो नम्बरों में उन को 180 या 160 या 170 नम्बर मिल जाते है और इस लिए ब्योरोक्रसी कभी नहीं चाहती कि समाज के अन्दर कोई बुनियादी तब्दीली आये। वह नहीं चाहते कि समाज के बुनियादी ढांचे में गरीबों को भी जमीन मिले, वह छोटे धंधे शुरू करें। आज हिन्दुस्तान का 90 परसेंट व्यापार बनियों के हाथ में है। कौन बनिया है जो उस को आसानी से छोड़ने को तैयार होगा। आज इन बनियों ने, इन सरमायेदारों ने देश के वेस्टेड इंटररेस्ट ने और ब्योरोक्रेसी ने मिल कर हम को हराया है और इस में सी आई ए का रुपया

लगा है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं है और न मैं ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि किस तरह से आप जीते है और कैसी बेईमानियां की गई हैं। किस तरह से एक वोटर ने चार, चार, छः छः वोट डाले हैं इस लिए कि अफसरों की हमदर्दी आप के साथ है। इसलिए नहीं कि आप ने काम किया है, इसलिए नहीं कि जनता को आप पर विश्वास है कि आप काम करेंगे, इसलिए नहीं कि आप काबिल है, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी गरज से किया है। नसबन्दी के प्रोग्राम की बात आप कहते है, लेकिन उस में कहीं देहातों में अगर जबरदस्ती हुई है तो उस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर, उस की पालिसी पर नहीं है। उस की जिम्मेदारी कुछ खुदगरज लोगों पर है, उन के खराब करेक्टर पर है। वह खुदगरज लोग जो जांत पांत मानते है उन्होंने छोटे छोटे आदमियों को पकड़ कर यह कराया है। तो यह हमारी गलती नहीं है। तो यह पालिसी की गलती नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियां है जिन को दूर किया जा सकता था। मगर जनता को गुमराह किया गया। देहात की जनता को गलत रास्ते पर रखा गया। उनमें गलतफहमियां पैदा की गई। उनसे जबरदस्ती काम लिया गया। आपने जात-पांत फैलाया चुनावों में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हरिजन बस्तियां थीं वहां पर आपने जगजीवन राम जिन्दाबाद के नारे लगाये। जहां पर ब्राह्मण बस्तियां थीं वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जिन्दाबाद के नारे लगाये। जहां पर जाटों की बस्तियां थीं, वहां पर चरण सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाये। मुझे बताइये यह कहां नहीं हुआ ? इस वजह से आप जीते है। तो जनता का यह शीशमहल चन्द दिनों में टूटेगा और आप देखते रह जायेंगे। आप क्या कर सकते है ? इतने साल हो गये, एक पार्टी भी आप इस देश में नहीं बना सके। आप अपने डिफरेंसेज को दूर नहीं कर सके। इन सब बातों की वजह से आज आप ताकत में है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते है कि आप सरकार को नहीं चला पायेंगे। आपकी पार्टी के अन्दर राजनारायण जैसे आदमी है जो एक पार्टी पर विश्वास रखता है। वह डिक्टेटर है सब से बड़ा। वह शख्स ऐसा है जो जहर फैलायेगा आपकी पार्टी में। चरण सिंह को मैं जानता हूं। जब एस० वी० डी० की गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस के आदमियों को तोड़कर तो मैं पहला शख्स था कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी में होते हुए मैंने चरण सिंह के मिनिस्टर को 60 वोटों से हराया। मानसिंह वर्मा को मिनिस्टर बनाया गया। वह ऐसा मिनिस्टर था जो न काउंसिल का मेम्बर था, न एसेम्बली का, लेकिन चरण सिंह ने उसको लिया था। मैंने उसको 60 वोटों से हराया, उसको इस्तीफा देना पड़ा।

This ultimately led to the total disintegration of the S.V.D. Government.

राजनारायण को मैं जानता हूं कि वह कैसा तानाशाह है। हम तो कुछ नहीं। हमारे मिनिस्टर तो अफिसरों से मिल कर काम करते थे। मैं जानता हूं राजनारायण तो उनकी कुर्सियां उलट देगा। र जनारायण थप्पड़ मार देगा उनको। वह किसी की नहीं चलने देगा, वह आपकी सरकार को कभी नहीं चलने देगा...

(Interruptions)

एक अफसोस की बात यह है कि राज आपने शुरू किया है वह हवा किस तरीके से शुरू की है वह देखने की बात है। डाइने-माइट केस जैसे मामले वापस लिये हैं। आप थोड़ी देर रुक सकते थे, अदालत फैसला करती और उनको बेकसूर करार देती और फिर आप कह सकते थे कि कांग्रेस ने उनको गलत गिरफ्तार किया, गलत केस चलाये। आपने आते ही उनके केस को वापस ले लिया।

[श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब]

यह डैमोक्रेसी है ? यह डैमोक्रटिक तरीका है ? फिर आपने क्या किया । आपने उनको मिनिस्टर बना दिया । कितना अन-डैमोक्रेटिक, अन-कंस्टीट्यूशनल यह काम आपने किया है । अदालतें चल रही है, आप फैसले सुन लेते । थोड़े दिन में फैसला हो जाता । लेकिन आपने केस वापस ले लिया । अपनी हुकूमत को बनाने के लिए आपने यह तरीका अख्तियार किया है ।

आपने एक बनी हुई काश्मीर एसेम्बली को भंग कर दिया । एक गवर्नर के कहने पर जो कुछ आपने किया है उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है उस पर कुछ नहीं कहना चाहता । मैं जानता हूं आप तोड़-फोड़ का क्या काम करेंगे । मैं जानता हूं इस तोड़-फोड़ से जो आप महल तैयार करेंगे वह रेत का महल ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा । मैं आपको यकीन दिलाता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह): कृपया समाप्त करिए ।

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब : मैं डिस्ट्रक्टिव पालिसी में विश्वास नहीं करता पर मैं आपको शुभकामनाएं जरूर देता हूं कि आप डैमोक्रेटिक तरीके से काम करें और आप सही रास्ता दिखायें । मगर यह जो केसेज आपने वापस लिये है यह ठीक नहीं है । जिस तरीके से असेम्बली को तोड़ा है वह ठीक नहीं है । मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है । मैं चाहता हूं कि एक आल्टरनेटिव पार्टी जो मजबूत हो, बने । उसकी एक ही आइडोलीजी हो, उसका एक डैफिनिट प्रोग्राम हो । हम जैसे गरीबों के लिए अछूतों के लिए और दूसरे शड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, वीकर सैक्शन के लिए एक खास प्रोग्राम होना चाहिए जैसा कि कांग्रेस के अन्दर है । आपने छोटे-छोटे बच्चों को पैसा देकर, रुपया दे कर जनता पार्टी जिन्दाबाद के नारे लगवाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है । आपने इनको गांव-गांव में फैला कर हमारे लोगों को तकरीर नहीं करने दी, उनको अपने विचार नहीं रखने दिये । यह सब आपने किया है और पुलिस ने भी आपका कोआपरेट किया है । ज्यादा न कहते हुए मैं आपका शुक्रिया दा करता हूं ।

SHRI K. S. MALLE GOWDA (Karnataka): Sir, with a feeling of great relief I welcome the great political change that has been brought about in the country by a great non-violent revolution through the ballot-box, India today is re-discovered and acclaimed by the world as the largest free democracy. The world has never had, in its record, a democracy where one party-rule continued for an unbroken period of nearly thirty years as in India. Power corrupts. And we can rightly add that power given to a political party continuously for over a quarter of a century corrupts to the core. This God-sent change was overdue to this country to ensure democracy in its true meaning to the great Indian people.

The inexorable political change unfolds the shining truth—the eternal truth that in a free democracy the people would come to reject any political party which would place itself above the country and sacrifice the interests and well-being of the people to nourish itself.

The greatest of the elections just ended in the largest of the free democracies of the world has thrown up another truth that, in a modern, enlightened age, it is free democracy which enshrines and ensures equality, human dignity, human development and freedom of the individual that the people would love, desire and fight for.

Sir, I strongly feel that the choice of Shri Morarji Desai as Prime Minister at this juncture in the troubled

history of India, was the best and the right one. The Prime Minister is a true follower of Gandhiji and is a strong advocate of human freedoms, individual liberty and is known to be a true democrat. He fears God and truth and these virtues in the leader of this nation are good enough to promise us a good 'janata raj' if not the ideal 'Rama Rajya' of our dreams.

Sir, we have before us the example of two great men of our country, Mahatmaji and Shri Jayaprakash Narayan, who loved the people of India and served them truly and selflessly, without so much as a thought for the throne at Delhi. It is the fervent hope of the Indian people—the youth, the old, the poor and the rich —that Janata Party and their allies will prove by their solidarity and solid work for the people, that they truly would worship the people and not power.

After the imposition of emergency, I had urged upon the former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, in this House, that 'political vendetta' should not be allowed to take root in this holy land of Bharata. I appeal to the present Prime Minister Morarji Desai and the Janata Government to show the 'divinity in man' and follow 'forget and forgive' policy in respect of the past unhappy events. There should be no witch-hunt.

I am sure that the good India people have greatly appreciated the greatness of Shri Jayaprakash Narayan and Shri Morarji Desai who called on the former Prime Minister.

Sir, I want to warn the new Government about two vital points. The Government should ensure strict price control in respect of articles of daily consumption as we, the poor and middle class families in the country, would feel the pinch of the price rise and would comment on the performance of the new Government.

Secondly, I want to remind the Government of its pledge to remove destitution in this country within a definite period of ten years. This pledge cannot be fulfilled if we do not take strong, emergent measures to check the population growth in our country with a package programme of incentives and disincentives simultaneously along with our plan to increase production in fields, factories, mines and oil-wells so that our GNP far outpaces the annual population increase.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि इस बजट पर भाषणों के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उन्हों ने रचनात्मक सुझाव देने का एक सामान्य सा आभास निर्माण करने का प्रयत्न किया है, उसकी कुछ झलक देखने को मिलती। मुझे अफसोस है कि मुझे इस बारे में बहुत बड़ी निराशा हुई है। भारत की जनता ने इस चुनाव में जो फैसला किया है, मैं समझता हूं कि बड़ी से बड़ी हस्ती के लिए भी यह एक बहुत बड़ी धृष्टता होगी अगर वह उसकी इज्जत न करे। यह कहना कि लोग बहकाव में आ गये, यह शायद उनके मुंह से कहा जा सकता है जिन्होंने इस जनता को बहकाने में बहुत दिनों सफलता प्राप्त की है। यह चुनाव हमारे देश की जनता की जागृति का परिणाम है। डर और धमकियों के वातावरण में भी उसने प्रजातंत्र को समझने का और अपने भविष्य को अपने आप बनाने का जो इस अवसर पर फैसला किया है, उसके लिए मैं सब देशवासियों को बधाई देता हूं। यह पहला मौका था जब लोगों को जात-पात के आधार पर बांटा नहीं जा सका शहर तथा गांव के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सका। इन चुनावों में सब प्रकार के सरकारी प्रलोभन और दबाव उनकी इंसानियत को खरीदने में असफल रहे।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उप-सभाध्यक्षा महोदय, क्या वे फाइनेन्स बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जब आपकी तरफ के माननीय सदस्य फाइनेन्स बिल पर अपना भाषण दे रहे थे तो हमने उनको शांति-पूर्वक सुना । इसलिए आप भी सुनने की कोशिश कीजिये । अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो अपने साथी से पूछ लीजिये ।

मैं यह मानता हूं कि इमरजेन्सी के हथियार से लोगों को डराया, धमकाया जा सकता है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि देश की आर्थिक परिस्थितियों को सम्भालने के लिए इमरजेन्सी का हथियार किस प्रकार से कामयाब हो सकता है । कुछ दिन तक तो . . . . . .

श्री प्यारे लाल कुरील (उर्दू तालिब) : मुल्क के अन्दर इमरजेन्सी इसलिए लागू की गई थी कि आप अराजकता फैला रहे थे । इसीलिए आपको गिरफ्तार किया गया था । कि आप पुलिस और फौज को बगावत पर उक्सा रहे थे

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : मैं समझता हूं कि चाहे कीमतें गिराने का सवाल हो, चाहे आवश्यक वस्तुएं साधारण आदमियों को उपलब्ध कराने का सवाल हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने का सवाल हो या मुद्रा-स्फीति रोकने का सवाल हो या नीतियों से संबंधित प्रश्न हों, इन पर पुलिस के डंडे से काम नहीं चल सकता है । हां, यह हो सकता है कि जो लोग चोर-बाजारी करें, जमाखोरी करें, माल को छिपाकर रखें, उनको डराने या धमकाने से कुछ काम चला हो, उत्पादन इससे नहीं बढ़ता । इमरजेन्सी लागू किये जाने के दो-तीन महीने तक डर के मारे आर्थिक परिस्थितियां सुधर रही हैं, यह आभास कराया गया लेकिन नीतियों के अभाव में कोई सही दृष्टिकोण लागू न होने के कारण विधायी सरकार आर्थिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकी । आज यह स्वीकार किया गया है कि इतनी लम्बी इमरजेन्सी के कार्यकाल के बाद भी कीमतें बढ़ी हैं, इनफ्लेशन बढ़ा और परिस्थिति आर्थिक क्षेत्र में काबू के बाहर होती चली गयी । आज भी 15 प्रतिशत से अधिक थोक मूल्यों के भाव में बढ़ोत्तरी हुई है और अगर हम पिछले सात वर्षों की नीतियों का विश्लेषण करें तो सात वर्ष पहले के मुकाबले में आज कीमतें दुगनी बढ़ गई हैं, टू हंडरेड परसेन्ट उसमें बढ़ोत्तरी हुई । जहां तक फुटकर मूल्यों का संबध है वह तो एक वर्ष में ही 33 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं ।

अब यह बात ठीक है कि पिछले दिनों में हमने काफी विदेशी मुद्रा कमाई और काफी अच्छा स्टाक सरकार के पास विदेशी मुद्रा के रूप में है । लेकिन यह किस कीमत पर हमने कमाया । जो कुछ देश मे आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध थीं विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के क्रम में हमने उसका निर्यात किया और इसके कारण अपने देशवासियों को उन चीजों के अभाव में हमने रखा । आज यह परिस्थिति पैदा हो गई है कि विदेशी मुद्रा इतनी इकट्ठी हो गई है कि देश में मुद्रा-स्फीति और देश में कीमतों को बढ़ाने का भी वह एक कारण बनती जा रही है । मेरा यह सुझाव है कि इसको एक डेड रिजर्व के रूप में न रखा जाय । आज भी देश की आर्थिक गति को तेज करने के लिये आवश्यक वस्तुओं के आयात की बहुत आवश्यकता है । इसके कारण यहां के उद्योग मंत्री को एक बहुत बड़ा बल मिल सकता है । जिस तरह से हमने अन्न का भंडार बनाया है, उसी प्रकार से एडिबल आयल और रुई के ऐसे भण्डार अगर हम बनाकर रखेंगे तो देश के उत्पादन को एक नई दिशा प्राप्त होगी । इसके कारण देश की मुद्रा-स्फीति पर भी दबाव पड़ रहा है उसको भी घटाने में मदद मिल सकती है ।

[The Vice-Chairman (Shri Lokanath Misra) in the Chair].

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमको जल्दी से जल्दी इस दबाव को, जो विदेशी मुद्रा के इकट्ठे होने से देश में हो गया है,

उसे देश की अर्थ रचना के लिये उपयोगी रूप दिलाने का प्रयत्न किया जाय ।

पिछले दिनों इस सारी आर्थिक रचना में मनमाने तरीके का दबाव, प्रतिबन्ध और तरह तरह की रुकावटें, देश की अर्थ व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने में बाधा के रूप में सामने आई । मैं चाहता हूं कि सरकार उन सब परिस्थितियों पर पुनर्विचार करे । देश में आवश्यक वस्तुयें हर व्यक्ति के पास पहुंचे इसका मैं समर्थक हूं । लेकिन अनावश्यक रुकावटें जितनी जल्दी हटाई जायेगी तो देश के सामान्य आर्थिक रचना के निर्माण में हम मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं । इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

सरकार की तरफ से पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो दो वर्ष बचे हैं उसमे भी किस प्रकार से प्रायरिटीज रखी जाय, किन-किन मदों पर प्राथमिकता से रुपया खर्च किया जाय, इसका सरकार विचार कर रही है । मैं चाहता हूं कि आने वाले पूरे बजट में जो एक-दो महीने के भीतर हमको देखने को मिलेगा उसमें इन प्रायरिटीज को बदल कर ही उसके अंदर रुपयों का प्रावधान किया जाएगा ताकि आज अनिवार्य रूप से जिन चीजों को प्राथमिकता मिल कर उनका उत्पादन होना चाहिए उसके लिए उस बजट में और राज्यों को मिलने वाले मद में उसकी पूरी गुंजाइश दिखायी दे ।

यह बात भी आवश्यक होगी कि जो हमारे सार्वजनिक संस्थान हैं उत्पादन के, उन में शत प्रतिशत उत्पादन की दिशा में हम कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं । उनके अन्दर लगाई गई शक्ति निरर्थक न पड़ी रहे, उसका पूर्ण उपयोग हो और उसके लिए जो इन्फ्राष्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है उसको तैयार करने के लिए हम सब प्रकार की प्राथमिकताएं किस प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं, इसकी भी उसमें व्यवस्था करें ।

ग्रामीण विकास, बहु-चर्चित होने के बाद भी, एक उपेक्षित विषय आज तक रहा है । मैं चाहूंगा कि अगले बजट में ग्रामीण विकास के ठोस कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाए । अगर मैं उसका एक उदाहरण दूं, तो आज भी इतने 25 वर्षों की देश की स्वतंत्रता के बाद भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । पेय-जल को प्राथमिकता दें और उसके लिए केन्द्रीय बजट में भी आवश्यक प्रावधान करना अनिवार्य प्रतीत होता है ।

जमीन काश्तकार को मिले, वह उसका मालिक बने, ये चर्चाएं तो बहुत हुई है, परन्तु इस क्षेत्र में ठोस पग उठाए जाने चाहिए क्योंकि केवल मालिक बनाने से ही काम नहीं चलेगा । सर्विस कोआपरेटिव्हस कायम करने होंगे, केन्द्रीय बजट में भी इसका प्रावधान करना होगा कि इस प्रकार की सर्विसेज को जो अग्रिकलचरिस्ट्स के लिए बने, उनकी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए जो मदद दे सके, उसकी व्यवस्थाएं बजट में होना आवश्यक है ।

कई ऐसे सूखे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा का अभाव है और अभी भी सिंचाई की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच सकी हैं । वहां पर हमे ड्राई फार्मिंग टैक्नालाजी की व्यवस्थाएं करनी होंगी । योजना में भी उसको प्राथमिकता मिले और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष में इस ड्राई फार्मिंग टेक्नालाजी को प्राथमिकता मिलेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा ।

ग्रामीण विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि अभी तक औद्योगीकरण का जो तरीका रहा है वह इस प्रकार से रहा कि ग्रामों के दूरस्थ अंचल अछूते हैं । जब तक हम पूरा का पूरा औद्योगीकरण का नक्शा नहीं बदलते, उसको विकेन्द्रित नहीं करते और कृषि के आधार पर विकसित करने का निर्णय नहीं

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

लेते और उसी के आधार पर प्लान प्रायरिटीज और बजट में उनकी आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकताएं हम नहीं देते, तब तक ग्रामीण विकास केवल एक चर्चा का ही विषय बन कर रह जाता है । चिंता केवल यहां भाषणों में व्यक्त हो कर रह जाती है पर उसके लिए कोई ठोस पग कहीं उठते हुए नहीं दिखाई देते ।

दूसरा ज्वलंत प्रश्न बेरोजगारी का है जो देश के अंदर बढ़ता चला जा रहा है । पिछले दिनों में ऋैश योजनाएं बनीं । माननीय सदस्यगण मुझे माफ करें अगर मैं कहूं कि यह एक स्थायी प्रश्न है, यह ऋैश योजनाओं से पूरा नहीं हो सकता । ऋैश योजनाओं से कुछ दफ्तर खुल जाते हैं, रुपये का ऊपर ही ऊपर बंटवारा हो जाता है लेकिन वास्तविक जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको वास्तव में नौकरियां मिलनी चाहिए या उनकी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए वह सब होने की बजाए ये ऋैश योजनाएं पब्लिसिटी ओरियेन्टेड ज्यादा है ; उनका लाभ ठीक व्यक्तियों को नहीं पहुंच पाता ।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस पंचवर्षीय योजना के बचे हुए काल में भी, और छठी पंचवर्षीय योजना के लिए जो भूमिकाएं बन रही हैं, उसमें "गिमिक्स" करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अब अगर वे सीधे सीधे ढंग से और विस्तृत स्ट्रक्चर के आधार पर, नीतियों के आधार पर इन बातों को अपने सामने रख कर चलेंगे तो उसमें से ही लाभ हो सकेगा ।

मैं केवल एक-दो सुझाव इस बजट के सम्बन्ध में देना चाहूंगा । मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों में कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम लागू की गयी थी उस के द्वारा, हम कर्मचारियों को आज की महंगाई की अवस्था में परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए राहत देते थे वह उनसे छीन कर हम ने उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है । मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इसके लिए मार्ग निकालें और कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम को समाप्त कर के जो कुछ पैसा कर्मचारियों का जबरदस्ती रोक लिया गया है वह उनको वापस दिलाने का प्रावधान करें ।

इसी प्रकार से जो महंगाई भत्ते की शर्तें पहले तय हुई हैं और कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के साथ उसको जोड़ा है उसके सम्बन्ध में भी पूरी राहत मिलनी चाहिए ।

रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय रेल मंत्री ने घोषणा की । जब तक लिविंग वेज का फार्मूला तय न हो जाय मैं चाहूंगा कि बाकी की सुविधाएं और सहायता देने का फार्मूला कुछ लिमिटेड लेबर तक सीमित न रहे, देश भर के सब मजदूरों पर और सब श्रमिकों पर उसे लागू करने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा ।

पिछले दिनों में यह तर्क दिया गया था कि क्यों कि इकानिमिक आफेंडर्स के खिलाफ देश के साधारण कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकते थे इसलिए हमें इमरजेंसी प्रावीजन्स का सहारा लेना पड़ा । पिछली सरकार बीस महीनों के लम्बे कार्यकाल में इमरजेंसी प्रावीजन्स के बिना इन आर्थिक अपराधों से कैसे निबटा जा सकता है इस के लिए कोई कांक्रीट स्टैप ले कर नहीं आ सकी और बिना अपराध बताये लम्बे डिटेंशन के द्वारा ही उन्होंने आर्थिक अपराधों से निबटने का तरीका बनाया हुआ था । अब इमरजेंसी हट गयी है । मैं इस के लिए बधाई देता हूं सरकार को । उन्होंने बाहर की इमरजेंसी को भी—बाहरी खतरे का जो हौआ बनाया हुआ था—समाप्त कर दिया । देश में कम्पलीट नार्मलसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी करने की छूट हासिल हो या आर्थिक अपराधों के लिए छूट मिली हो या समाजविरोधी तत्वों

को गड़बड़ करने का मौका मिले । मैं चाहूंगा सब क्षेत्रों में और विशेषकर आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में कानूनों का जल्दी से जल्दी अध्ययन हो और अगर इन आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कानून की सीमाएं किसी प्रकार से छोटी दिखायी देती हों, तो यह पहला काम होना चाहिए सरकार का कि कानूनों को इतना सशक्त बनाये कि इन आर्थिक अपराधों को रोका जा सके । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इमरजेंसी प्रावीजन्स का आश्रय लेकर नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त करने के और बिना मुकदमा चलाये कैद में रखने के जो पग पिछली सरकार के द्वारा उठाये गये उन की सम्भावना ही न रहे । इस चुनाव में अगर लोगों ने किसी चीज़ को बदलने की कोशिश की है तो इसी स्थिति को बदलने की कोशिश की है । और जो फैसला उन्होंने दिया है इस सरकार को उस से अपनी ताकत ग्रहण करनी चाहिए । कानूनों को अपटुडेट बना कर सारे देश की जनता को ऐसे अपराधों के चक्कर से बचाने में सरकार सफलता प्राप्त करे यह हमारे कार्य का उद्देश्य होना चाहिए ।

मैं वित्त मंत्री महोदय को उन की इस नयी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और चाहूंगा कि आने वाले बजट में जो मैंने सुझाव दिये हैं उन के सम्बन्ध में ठोस पगों का नक्शा वे उपस्थित कर सकें । धन्यवाद ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप सभाध्यक्ष जी, भारत के वित्तीय इतिहास में सब से छोटा भाषण जनता पार्टी के वित्त मंत्री का है । उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि जो बजट तैयार हुआ है वह उनके दृष्टिकोण के मुताबिक नहीं है इस लिए आगे के बजट में अपने दृष्टिकोण को दर्ज करेंगे । आगे वह कैसा दृष्टिकोण रखना चाहते हैं यह तो हम को मालूम नहीं है इस लिये कि उन्होंने इस बात का कोई ब्योरा नहीं दिया है । लोगों को वह गलत आशायें देना चाहते हैं या लोगों की आर्थिक स्थिति को सही तौर पर मजबूत करना चाहते हैं यह तो आगे आने वाला समय बतायेगा, लेकिन जैसी आज सदन में बहस हुई, जम्मू कश्मीर के बारे में कि पार्लियामेंट को भी अधिकार न हो जो संविधान में होना चाहिए था यह अजीब बात है । वहां एक शख्सी हुकुमत कायम की गयी जिस को—कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया । वह किस इरादे से की गयी यह तो आगे आने वाला समय बतायेगा । इसी इरादे को वह आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं यह भी आगे आने वाला समय बतायेगा । उनकी जो बजट स्पीच है वह बहुत छोटी है इसलिये कि लोग सोच न सकें । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता भंडारी जी ने जिक्र किया कि आपात स्थिति में जो कुछ बातें हुई थीं उन की वजह से कांग्रेस पार्टी को हार खानी पड़ी यह बात सही नहीं है । मैं जानता हूं कि उनके बड़े बड़े नेता हमेशा एक ही बात की दुहाई देते रहे । उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आपात कालीन स्थिति में हुए नुकसान को लोगों को बतायें, वह एक ही बात की दुहाई देते रहे—परिवार नियोजन की और उस में हुई ज्यादतियों की । उसके अलावा बड़े से बड़े नेता ने भी कोई दूसरी बात नहीं कहीं । मैंने सभी बड़े नेताओं के भाषण सुने हैं । वह केवल चुटकियां देते थे कि अगर कांग्रेस वाले आयें तो कहो कि 'दो केस दो, एक वोट लो' । इस मजाक में हिन्दुस्तान का चुनाव हुआ और उस के नतीजे पर आज हमारी सरकार के वजीर और दूसरे साथी खुश हैं । लेकिन उनकी यह खुशी बहुत दिन नहीं ठहरने वाली है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आगे जो बात मैं कहना चाहता हूं वह नयी बात नहीं है । जब उधर बैठता था तब भी कहा करता था ।

(श्री रणबीर सिंह)

जहां तक हमारे वित्त मंत्रालय का संबंध है उस की सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश ने माना है कि का हम को, देश में समाजवादी आर्थिक ढांचे को लाना है लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय पिछले तीस साल से और आज भी उसी चक्कर में हैं जिस को मरकेंटाइल इकोनामी का जमाना कहते हैं। वित्त मंत्रालय की सोच समाजवादी नहीं हुई है। हमारे देश में आज भी कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को जो राज दिया है वह कितनी मजबूत हालत में दिया है यह देखने की बात है। हमारे पूर्व वक्ता ने इस बात की कोशिश की कि दो हजार करोड़ विदेशी रुपया, जो यह सरमाया हम ने छोड़ा है, उस का उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की। मैं उन को बताना चाहता हूं कि मैं इस सदन का मेम्बर था जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी और खास तौर पर भंडारी जी जिस पार्टी से पहले संबंध रखते थे, जिस का नाम जनसंघ था, उस के जन्मदाता श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी थे। उन की बात मुझे आज भी याद आती है। पहली पंचसाला योजना के बारे में उन्होंने कहा था कि उस के अंदर सिर्फ ढाई सौ करोड़ रुपये को विदेशी सहायता का जिक्र था।

उन्होंने कहा था कि न अमरीका इनके साथ है, न रूस इन के साथ है, इनको कौन देगा। ये तो बहकावे की बातें हैं और आज हम दो हजार करोड़ रुपया विदेशी सरमाया उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं, 2300 करोड़ रुपया छोड़कर जा रहे हैं। तो बजाय इसकी तारीफ करने उनको मजाक में उड़ाने की कोशिश की है। एक दफा तो मजाक में जीत गये। मजाक के अन्दर लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप इस बात को समझें। मैं मानता हूं कि हमने 30 वर्ष तक इस देश का आर्थिक ढांचा बनाने की कोशिश की है और मजबूत ढांचा बना कर आपके हाथ में देकर जा रहे हैं। मुझे याद है जब 1947-48 के अन्दर जो हिन्दुस्तान का बजट था वह सिर्फ 900 करोड़ रुपये का बजट था और 300 करोड़ रुपये का डिफेंस का बजट था। आज जब हम छोड़कर जा रहे हैं तो 14 हजार करोड़ रुपये की टैक्स की आमदनी होगी, ऐसी मजबूत हालत में हम आपको सौंपकर जा रहे हैं। 14184 करोड़ रुपये की आय आज होगी।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : छोड़कर कहां जा रहे हैं?

श्री रणबीर सिंह : आपके हाथ में दिया। छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपकी आंखों में हमेशा हम खटकते रहेंगे। आप के लिए यहां आकर भूत हम बने रहेंगे। लेकिन भूत हमको मानकर आप सही देश के काम को चलायें तो उसमें हमें खुशी है। हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश को 10-11 साल के अन्दर मजबूत किया। ग्रामीण इलाकों की बात कही जाती है। जब वह प्रधान मंत्री बनी थीं इस देश के अन्दर 75 हजार गांवों से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं गई थी। जब वह गई हैं तो पौने दो लाख गांवों के अन्दर बिजली का प्रसार करा कर गई हैं। जब वह प्रधान मंत्री बनी थीं उस वक्त सिर्फ 10 लाख पम्पिंग सैट थे, जब वह गई हैं, देश में 28 लाख बिजली से चलने वाले पम्पिंग सैट छोड़कर गई हैं। जब वह प्रधान मंत्री बनी थी उस वक्त हिन्दुस्तान की जो बिजली पैदा करने की शक्ति थी वह 20 लाख किलोवाट की थी, जब वह गई हैं तो वह 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की शक्ति बनाकर गई हैं।

आज देश आपकी तरफ देखता है। आपने बड़े वायदे किये थे। आपने लोगों को बताया था कि हिन्दुस्तान की कांग्रेस ने देहातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हम आपकी तरफ देखना चाहते हैं कि आप कैसा करेंगे, कैसा न्याय किसान के साथ करेंगे।

आपने जिक्र किया था आज हमारी खती के वजीर अग्रिकल्चर मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिह बादल साहब करनाल जिले में गए थे और जेल के दरवाजे खटखटाये थे यह कहते हुए कि 105 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम थोड़ा है । अब हम देखते हैं कि बादल साहब का न्याय कैसा है, किसान को कितना पैसा मिलने वाला है और किसान के ट्रैक्टर के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, जैसा कि एक समय था जब कि बाहर से जो ट्रैक्टर आते थे उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं थी, लेकिन देश की कुछ आर्थिक हालत ऐसी आई कि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ी, कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर लगानी पड़ी और जब आपके हाथ में काम दिया तो आर्थिक ढांचा देश का मजबूत है और आज हम देखना चाहते हैं कि ट्रैक्टर पर से आप एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं कि नहीं ।

ट्रैक्टर पर कितनी एकसाइज ड्यूटी घटाते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप का काम भी वही वित्त मंत्रालय में काम करने वाले चलायेंगे जिन्हें कार की फिक्र है, देश में अनाज पैदा करने की फिक्र नहीं है । देश में अंदर अनाज कैसे पैदा होता है इस बात की उनको फिक्र नहीं है । इसीलिये कीमतें घटी हैं कारों की, ट्रैक्टरों की नहीं घटी । आप भी इम्तिहान में आने वाले हैं । जब आप हम को मानते हैं कि हम इम्तिहान में पास नहीं हुए हैं तो आपको भी देश देखेगा कि आप कैसे इम्तिहान में पास होते हैं । आप जानते हैं मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री एक बार चौधरी बंसीलाल थे जिनका नाम विरोधी दल के सदस्यों को अखरता है लेकिन इस बात से विरोधी दल के सदस्य इंकार नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान का वही सबसे पहला प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर बिजली पहुंची है, जिस प्रदेश के अंदर 60 फीसदी गांवों के अन्दर सड़कें पहुंची हैं । अब हम आपको देखना चाहते है । अब चौधरी चरण सिंह जी इम्तिहान में आए हैं, उनको हम देखना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह का अब छारोली इलाका नहीं है, बागपत का इलाका है, उसमें कितने अर्से में बिजली पहुंचाते हैं, कितने अर्से में सारे गांव के अंदर सड़कें पहुंचाते हैं । जमुना हमारे बीच में है । आप याद रखिये कि इन चुटकियों से बहुत दिन काम नहीं चलेगा । चुटकियों से चुनाव एक दफा जीता जा सकता है बार-बार चुटकियां लगाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता । यह तो इतिहास की बात हो गयी कि परिवार नियोजन इतिहास की बात हो गयी कि परिवार नियोजन के अंदर ज्यादतियां हुई हैं । मैं चाहता हूं कि आप जरा इस बात का ब्यौरा दें क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार में कभी यह नहीं कहा था कि ज्यादतियां हों । उन्होंने, चुनाव के वक्त में जब उनको पता लगा कि परिवार नियोजन प्रोग्राम चलाने में देश के अंदर कुछ ज्यादतियां हुई हैं, आश्वासन दिया था कि उन आदिमियों के खिलाफ जिन्होंने परिवार नियोजन के अंदर ज्यादतियां की है, गैर कानूनी कार्रवाइयां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । अब आपके हौंसले का इम्तिहान है कि आप आई०सी०एस०, आई०ए०एस०, आई०पी० एस० आफिसरों से डरते हैं या उनकी गलतियों पर उनको सजा देते हैं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आपने सजा दिलवाई थी ।

श्री रणबीर सिंह : आप तेजी न दिखाएं । अभी बहुत समय है । छः साल का समय है । आप छः साल चलते हैं या नहीं चलते हैं यह भी देखने वाली बात है । उत्तर प्रदेश की सरकार टूटती थी तो केन्द्रीय सरकार को बदनाम किया जाता था । अब आपकी सरकार, जो खिचड़ी की सरकार है कब तक चलेगी

(श्री रणबीर सिंह)

यह संसार और भारत देश देखेगा । हम चाहते हैं कि आप कामयाब हों इसलिये कि आपकी कामयाबी से देश की तरक्की होगी । हम कुर्सियों के भूखे नहीं हैं लेकिन यहां कुर्सियों के भूखे आपस में लड़ते रहते हैं और यह आने वाला इतिहास ही बताएगा । किसानों की बात करने वाले, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने की बात करने वाले कितने कामयाब होते हैं यह इतिहास ही बताएगा । आपको याद होगा कि जब हम उधर बैठते थे तब भी यही बात किया करते थे । आप मेरी बात की ताईद करेंगे । आखिर में, मैं एक प्रार्थना करता हूं कि यह वित्त मंत्रालय की जो सलाह है इसको आप छोड़ दें अगर आप चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सही हो । देश की अर्थ व्यवस्था सही हो । यह जो तनख्वाहदार भाई हैं इनके दबाव में आना छोड़ दें । यह देश तनख्वाहदारों का देश नहीं है यह देश गरीबों का देश है जिन गरीबों की आमदनी 30 रुपये महीना भी नहीं है । उनके लिए आप क्या करते हैं, उनको किस हद तक ऊपर उठाते हैं, जरा यह देखने वाली बात है । मैं कहता हूं कि हमारे देश ने जो शक्ति पैदा की है, जो बिजली पैदा की है और हमारे देश ने जो बिजली के यंत्र पैदा किये हैं उनको अब लगाइये । मैं समझता हूं कि आज जो यह कहा जाता है कि यह डेफिसिट बजट है, घाटे का बजट है और यह जो नोट का चक्कर है, इसको आगे देखने की जरूरत है ।

आखिर में एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि समाजवाद के अन्दर क्या होगा ? समाजवाद के अन्दर हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ खुलेंगे उनके बाजू खुलेंगे और हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा । आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो शक्ति है, जो सम्पत्ति है, उसके बारे में हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी मंहगाई बढ़ गई है, इसलिए उनकी मंहगाई बढ़ाई जानी चाहिए । जिस तरह से हमारे देश में मंहगाई की मांग बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यह मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है । इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हिसाब लगाकर योजना बनाई जाये हम जितने यंत्र पैदा कर सकते हैं, जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं उनको पैदा करें । हमारे देश में चाहे ईंटों का सवाल हो, कोयले का सवाल हो, अनाज का सवाल हो, या अन्य कोई दूसरा सवाल हो, हमें सबसे पहले अपनी खेती की तरफ ध्यान देना चाहिये । हम आपके लिए दो करोड़ टन अनाज का भंडार छोड़ कर गये हैं । इसी तरह से कोयले का भंडार है, लोहे का भंडार है । हमें अब आगे यह देखना है कि आप देश का शासन किस तरह से चलाते हैं ।

एक और बात मुझे कहनी है । मुझे यह मालूम नहीं कि किस की कार्यवाही से यह कार्य हुआ है । हमारे यहां जो सीमेन्ट के बोरे हैं उनकी कीमत फी बोरा 10/- रु० बढ़ गई है । यह कैसे बढ़ गई, यह बात समझ में नहीं आती है । कोई मैं प्रशासन को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप गलत नीतियों पर चलेंगे तो आपको भी वही नतीजा भुगतना पड़ेगा जो हमें आज देखना पड़ रहा है क्योंकि हमें जो सलाह देने वाले भाई थे, जो हमको सच्ची बात नहीं कहते थे, उनके बहकावे में हम चले । मैं चाहता हूं कि आप देश को आगे बढ़ायें और देश की तरक्की करें ।

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I take this opportunity, first of all, to congratulate the people of India who have struggled by ballot and emancipated themselves from the tyrannical regime. I welcome the Finance Minister's speech because he has plainly stated that the Budget did not reflect the philosophy, politics

and programmes of the present Government. The reason is lack of time, and . . .

SHRI RANBIR SINGH: There is no policy, because it is *khhichri*.

SHRI P. K. KUNJACHEN: In the President's speech it is stated in which direction the Government is going to move, namely, the MISA, the amendment to the Representation of People's Act, the 42nd amendment to the Constitution, etc., will be reviewed, and the PPOMA will be revealed. He has further stated that people were against authoritarian rule and also against the development of extra-constitutional powers.

Sir, the election result is very clear. The southern States have not come up as the northern States have done. Elections were not conducted for the Assemblies in Tamil Nadu and also in Pondicherry. Election was conducted for the Kerala Legislative Assembly only.

Sir, so many malpractices have been committed by the ruling front headed by Congress in Kerala elections. I am not going into the details. But I wish to bring to the notice of the Government that Government must request the Chief Election Commission to go into details. Sir, the paper used for the printing of ballot papers has been removed from the Government press and also the ballot papers have been printed in private presses. It has already been distributed in every polling booth for committing malpractices. There is another thing which is also against the eletcion rules. Communal feelings had been raised at a high level. The ruling front tried to create hatred between Muslims and Hindus stating that the Jana Sangh is against the Muslims and Vice-virsa. A cartoon has been published in 'Chandrika', a daily paper, in which a pig is shown. A portion of the flesh has been cut. It is taken by Comrade E.M.S. Namboodripad and it is being given to the opposition Muslim League Leader. Such things have happened throughout the State. That was the propaganda which has been done. After the elections, there is no rule of law in Kerala. The Central Government must take a serious note of this thing. In Alleppey District, the house of the Secretary of the C.I.T.U. Zila Committee was raided by Congress goondas. His wife was taken out and assaulted. Similary, so many instances have taken place in Cannanore District. I am not going into all the details. So many atrocities have been committed. Congress goondas are joining together and attacking the opposition people there with the help of police. The Government must conduct inquiries about this at the earliest.

SHRI KALP NATH RAI: Why is he saying Congress goondas? Kindly ask him to be goodmannered.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): He has not called the Congress as goondas. Those who have done those things have been called goondas.

(*Interruptions*)

SHRI KALP NATH RAI: Don't say like that. You are a**. If he says that Congressmen are goondas he is a**.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): You had your say, Mr. Kalp Nath. Now you must resume your seat.

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar): Some unparliamentary words have been used. They should be expunged.

(*Interruptions*)

**Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): He is on a point of order. Let us hear him.

SHRI KALP NATH RAI: This man has three times said "Congress goondas". Why has he said that? He could not say so.

डा० रामकृपाल सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या कोई इस सदन का माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य को * कह सकता है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): If anybody has addressed another Member of the House in a derogatory term, that has to be expunged.

SHRI KALP NATH RAI: Any other party also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Mr. Kunjachen, it would be in good taste if you do not accuse any party member as goonda element. That would be in good taste in a parliamentary democracy.

SHRI P. K. KUNJACHEN: I never mentioned any party member but the goondaism that had been committed by the Congress people. That is what I meant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): That is the difference.

SHRI KALP NATH RAI: It is quite different.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Now he has changed his version. Let him go ahead.

SHRI SULTAN SINGH (Haryana): whatever he has said is not in good taste.

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Now you have heard what he has said. Let him go ahead.

SHRI P. K. KUNJACHEN: Sir, the 42nd Constitution Amendment must be repealed first. Then we will have to think of changing the Constitution or bringing about some amendments. First of all this 42nd Amendment to the Constitution has to be withdrawn.

Similarly, Sir, there is another thing. It is understood that even now certain political prisoners are in jails. They must be released immediately. A general amnesty must be proclaimed and all the political prisoners, whoever they might be, must be released from the jails immediately.

Sir, the most urgent problem before the country and the Government is the rise in prices and also the unemployment problem. Immediate steps must be taken by the Government to bring down the prices of essential articles. It is now understood that the price rise has gone up by 15 per cent in the recent past. So, immediate steps are needed in this direction. Steps may be taken to solve unemployment problem also.

Sir, in this connection, I wish to bring to your notice certain important issues relating to Kerala. In Kerala, our hereditary industries are in a crisis. Take the case of cashew industry. Sir, before the declaration of emergency there were 180 days of work per worker per year in the cashew industry. After the emergency they have been reduced to 80 days a year because the cashew nut has not been purchased from Africa and it has not been brought to Kerala. Two lakhs of workers are depending on this industry. This year also the same will be the position. There would be only 80 days or 70 days of work per worker. Similarly, the coir industry is also in a crisis. A plan has been submitted by the previous Government itself for sanction-

ing Rs. 15 crores for the uplift of this industry. But it has not been sanctioned and the coir industry is suffering. Similar is the case with the handloom industry. About Rs. 30 or 40 crores worth of crape cloth is in stock as there is no market. In fact, all the people working there who belong to the INTUC, the CITU and the AITUC are demanding that some rehabilitation work should be taken up for these handloom workers.

Sir, to talk of big industry, there are very few big industries in Kerala. So, Sir, this Government must consider starting of some industries in Kerala so that the unemployment problem could be solved at the earliest. The Central Government has fixed a target of ten years to solve the unemployment problem.

Sir, in the President's Address, it is said that the Government will take a completely neutral stand in its relations with other countries. Even though I subscribe to that idea, at the same time, I wish to bring to the notice of the House that we must be aware of the stand taken by the imperialist forces. It is the imperialist forces who fought against Vietnam and its people for a long time. It is the imperialist forces headed by Amercia which have overthrown the Allende Government in Chile. Sir, it is the imperialist countries which are building military bases in Diego Garcia. We should not forget these things. So, when we consider this aspect, we must remember that it was the socialist block which came to our help, and not the imperialist countries, for building up the economic plans and for the defence of the country. So it is important that when we consider of our relationship, we bear these things in mind. With these words I conclude, Sir. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Shri Sardar Amjad Ali, not here. Yes, Shri Schamnad.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Budget that has been presented before the House by the hon. Finance Minister. The hon. Finance Minister has made it clear that the Budget and the Demands for Grants that are presented were prepared on the basis of the directions given by the previous Government and it has been made clear in the Budget Speech itself that they do not reflect the policies and programmes of the present Government. It is gratifying to note that all the Ministries and Departments of the Government as well as all the public sector agencies will be asked to observe utmost economy in expenditure and that the present Government would emphasise austerity and avoidance of all forms of ostentatiousness.

Sir, this Government has emphasised the necessity of maintaining the freedom of the people and respecting the rights and liberties of the common man. I am very glad that the Government has taken steps to see that whatever obstructions were there on the freedom of the people those are removed and freedom is given to the people of our country. At the same time, I would like to say, Sir, that it is not only the political and other freedom which are important but the economic freedom is also very important and should be given to the people. I am quite sure that the Janata Government will work in that direction and see that people are not economically exploited. At present exploitation from big houses, big landlords and big industrialists is there and that exploitation should be put a stop to once and for all. I am quite sure that the present Government headed by Shri Morarji Desai will work in that direction and see that the common man is free from economic exploitation. Today landlordism is prevailing in our land and in many States bossism by the feudal

[Shri Hamid Ali Schamnad]

lords is continuing. All these people should be free and land reform measures should be implemented not only in letter but in spirit also. Even though some land reform measures have been implemented, full action has not yet been taken and I would therefore appeal to the Government to see that all the necessary land reform measures are implemented and land is given to the tiller who tills the soil. I hope the Government would work in that direction.

I may stress an important point with regard to the rural economy of the country. Today the rural economy of the country is upset and the cultivator being the backbone of our country, his interest should be safeguarded. Today the prices of agricultural produce are falling and, at the same time, the prices of foodgrains are also falling. It is a very delicate position as far as foodgrains are concerned. The number of consumers in our country is very large and most of them are poor people and therefore the prices of foodgrains cannot be raised beyond a certain level. It is therefore essential that the price of fertilisers and the cost of production of foodgrains should be curtailed. For that, Government should formulate a policy to see that economic price is fixed for the foodgrains.

6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Mr. Schamnad, how long will you take? Would you take about two or three minutes more?

SHRI OM MEHTA (Jammu and Kashmir): Let him finish, Sir, We will sit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): All right.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Thank you for the gesture.

Then, the cost of the fertilizer is going very high and the cost of agricultural implements also is going up but the cost of agricultural produce, especially, the foodgrains, is coming down. So, there should be a balance to see that a cultivator who produces foodgrains, gets an economic price, a price by which he could carry on his normal life, because, he has to do his cultivation, clear his debts and look after his children. For that, a national economic price should be fixed. I appeal to the Government for that.

Credit facilities should be extended to the small farmers. Much has been said by the previous Government about opening rural banks to help the small farmers as if the entire farmer community is getting that credit facility. Such a propaganda has been carried on in the country that everywhere they have opened rural banks. But, actually, not even half per cent of the needy people in the country are being given this credit facility. Adequate funds may not have been available. For that, more funds should be made available so that the needy farmers are given the credit facilities.

Supply of electricity at a cheaper rate also should be arranged for the farmers. Underground water should be lifted and made available to the farmers. We have got a lot of resources which have got to be exploited and, therefore, I suggest that underground water should be lifted, thus converting dry lands into wet lands. There has got to be a proper scheme for converting dry lands into wet lands. Pump sets should also be freely supplied to the farmers.

Another thing which I wanted to urge upon the present Government is to have a crop insurance scheme. This scheme would benefit the farmers. If, today, the crop is destroyed because of some natural calamity and because of other reasons beyond the farmer's control, the farmer has no other source of getting compensation. If a crop insurance scheme is started, there would be a security for the toil

and labour put in by him. Crop Insurance scheme should be one of the programmes of this Government and the Finance Minister should see to the practicability of having such a scheme.

Another thing is, the present Government, the Janata Party's Government are going to set up a Minorities Commission. It would be a boon to the minority communities in the country. I am sure the Janata Government headed by Shri Morarji Desai would definitely appoint a Minorities Commission and that too, as he said, it would be a permanent Commission. I really welcome the gesture of our beloved Prime Minister Shri Morarji Desai when he said that such a Commission is going to be appointed. The entire Muslim community of this country would be grateful to the Prime Minister Shri Morarji Desai and his colleagues for appointing this Commission so that the grievances of the minority communities are redressed. As far as lawlessness in the States like Kerala is concerned, I would like to add to the sentiments expressed by the previous speaker, Mr. Kunjachen. These rowdy elements are there. I do not say that they belong to this party or that party. But they should be checked. The political parties should not encourage such rowdy elements. Simply because the Kerala Ministry is headed by a Congress Chief Minister, it does not mean that the Congress Party should encourage the rowdy elements in the Kerala State. If they encourage, the Centre should step in and see that the State Governments do their duty. Lawlessness in the country should be dealt with firmly. We speak about giving freedom to the common man and all that. But at the same time, I would say that freedom should not be given to such an extent that chaos and confusion is created everywhere. We should not give too much freedom to the Police. Freedom should be curtailed in the larger interests of the people so that there is no chaos and confusion. I would appeal to the Home Ministry to see that the lawlessness is dealt with wherever it is prevailing. If the State Governments do not do their duty, the Central Government should step in and see that the atmosphere of cordiality and peace is restored and maintained throughout the country.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

I. The Appropriation Bill, 1977;

II. The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977;

III. The Tamil Nadu Appropriation Bill 1977;

IV. The Tamil Nadu Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation Bill, 1977, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 1977.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 1977.